Division. Just for the benefit of the hon. Member, I might add that this need was felt because these days at the airports, there are not only requirements of prior X-ray, tagging and complex documentation, both for sending the bags and for receiving the bags, but there are also formalities such as preparation of Bill of Exchange, customs clearances, etc., before the airport authority accepts the bags or Airlines delivers the bags. No security aspect has been compromised, and it would not be correct to say that only because of the cost factor and efficiency, this has been done. This was found to be practical and it is functioning well.

*252. [The questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent for answer *vide* page 53–66 infra].

सी॰आई॰एल॰ द्वारा कोयले की नीलामी

*253. डा॰ मुरली मनोहर जोशी:††
श्री राम जेठमलानी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षो से कोल इंडिया लि॰ द्वारा कोयले की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब शुरू की गई थी और कितनी बार नीलामी के माध्यम से कोयला बेचा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त नीलामी के दौरान फ्लोर-प्राइज, नोटीफाइड कोयले की कीमत से अधिक तय की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन) (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लि॰ (बी॰सी॰सी॰एल॰) में नवम्बर, 2004 में परीक्षण आधार पर ई-नीलामी शुरू की गई थी तथा धीरे-धीरे उसे मई, 2005 तक सभी कोयला कंपनियों में लागू किया गया था। जुलाई, 2006 तक कुल 604 नीलामियां की गई।

††सभा में यह प्रश्न डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

(ग) और (घ) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादन सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की बाजार निर्धारित कीमत की वसूली करने के उद्देश्य से यह किया गया था।

Auction of coal by CIL

†*253. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for the last couple of years coal is being sold by Coal India Ltd;

(b) if so, when was the said process introduced and number of times coal has been sold through auction;

(c) whether it is also a fact that floor price was fixed at higher rates than the price of notified coal during the said auction;and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COAL (SHRI SHIBU SOREN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. E-auction, on trial basis, was started in Bharat Coking Coal Limited (BCCL), a subsidiary of Coal India Limited in November, 2004 and was gradually extended to all coal companies by May, 2005. Till July 2006, a total of 604 auctions have been held.

(c) and (d) Yes, Sir. It was done to enabl realization of market determined price of coal by the coal producing subsidiaries of the Coal India Limited.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, इस प्रश्न के उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि ई-नीलामी से पहले नीलामियों की संख्या कितनी हुआ करती थी और उसमें छोटी मात्रा की नीलामी करने वाले कितने बिडर्स होते थे और बड़ी मात्रा के लिए, लॉर्ज क्वांटिटी के कितने बिडर्स होते थे? इस तरीके की वजह से, जबसे आपने इसको सभी कंपनियों में लागू किया है, क्या सिर्फ बड़े खिलाड़ी मैदान में रह गए हैं और जो छोटे बिडर्स थे, वे मैदान से बाहर हो गए हैं? क्या यह बात सच है?

श्री शिबु सोरेन: सर, यह जो बिक्री की पद्धति है, वह कोल इंडिया में तैयार होती है। ..(व्यवधान)... आंकड़ा देखकर बोलेंगे, लेकिन पहले ऐसा नियम था कि लोगों को लिखकर

† Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

दिया जाता था, कोयले की विभिन्न तरीके की चीज बनाने के लिए छोटे-छोटे कारखाने या बड़े उद्योगों के लिए भी। जब कोयला कंपनी में कोयला घट गया, जब नहीं दिया जा सका, तब यह बात उठी और श्री विजय कुमार पोद्दार कोर्ट में चले गए। उस समय कोर्ट के ऑर्डर से यह ई-नीलामी का हुआ, ताकि जिसको जरूरत हो, उसको मिलना चाहिए। अभी जो लिंकेज विधि बनी है, इससे कंट्रोल होना चाहिए। यह बात है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, मेरा प्रश्न यह था कि पहले बड़े खिलाड़ी कितने होते थे और छोटे खिलाड़ी कितने होते थे? क्योंकि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी मात्रा के लिए बिडिंग करते थे, छोटे खिलाड़ी छोटी मात्रा के लिए करते थे। इनकी कितनी संख्या थी।

श्री शिबु सोरेन: सर, पहले जो था, कोयले की अधिक मात्रा होती थी और यह उस समय की बात है, जब लोग जगह-जगह पर घाटकोप वगैरह बनाते थे, तो उन लोगों को देने में उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। कोई खिलाड़ी नहीं थे और अभी भी कोई खिलाड़ी नहीं हैं, जो नियम बनाया गया है। यह ई-ऑक्शन की व्यवस्था खिलाड़ियों से बचने के लिए ही की गई है और यह भी कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट हुआ था, उसके आधार पर है, किन्तु यह भी अभी ट्रायल पर है। अगर इससे भी असुविधा होगी, तो फिर कोई दूसरा उपाय किया जा सकता है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, इस नीलामी के तरीके से आपने कहा है..

श्री सभापति: आपके दो क्वैश्चन्स हो गए हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: नहीं, सर, पहला सवाल हुआ है। तो आपने कहा है कि मार्केट डिटरमिंड प्राइस मिलने के लिए इसको किया गया है। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि अब इस तरीके से कोल इंडिया और उसकी सबसिडिअरीज को कितना मुनाफा हो रहा है? कितना ज्यादा पैसा उनको मिल रहा है? और, दूसरा उपभोक्ताओं को कितनी ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है?

श्री शिबु सोरेन: सर, यह तो समय पर ही किया जाएगा। ...(व्यवधान)... वह जो कोयला देने की बात है, जिनको जरूरत है उनको तो कोयला देना ही पड़ेगा जिसने कारखाना बनाया है।

श्री सभापति: बिलकुल सही बात कह रहे हैं। आपको संतुष्ट होना चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। क्वैश्चन मेरा नहीं है, क्वैश्चन तो आपका है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मेरा क्वैश्चन है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। ...(व्यवधान)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कोयला खदान के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला महंगा हो गया और महंगा होने का मूल कारण था कि जो व्यापारी बीच में आए, जिनको बड़े एलोकेशन मिलते रहे और डीओ लेटर को लेकर वे

लोग ब्लेकमार्केटिंग करते रहे, उसको रोकने के लिए सीआईएल ने एक नया तरीका अपनाया, जिसमें ई-ऑक्शन और ऑक्शन का माध्यम लिया गया, परन्तु इससे बड़े-बड़े व्यापारी फिर मार्केट में आ गए। अब जो इंडस्ट्री कोल-बेस्ड है, जिसका रा-मैटेरियल कोयला है, कोयला जिसकी ऊर्जा है, ऐसी जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आपने क्या प्रावधान रखा है? क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (DR. DASARI NARAYAN RAO): Sir, through you, I would like to reply to the hon. Member that the e-auction was introduced because there are many bogus linkages. We have conducted a meeting in Kolkata and we referred to the bogus companies and we found that about 680 companies, out of 1250, were taking the linkages. Then, we have taken a decision to make it transparent. So, the e-auction was introduced. Actually, Sir, as the hon. Member mentioned it, we are, under the leadership of the hon. Prime Minister, taken a decision that small, tiny consumers should not get affected when this e-auction who cannot participate in this e-auction. So, we have separately given 3 million tonnes to State Governments and 2 million tonnes to NCCF. That means, we have provided 5 million tonnes for the tiny, small consumers... *(Interruptions)* NCCF is not a private company, it is under the Ministry of Food Processing Industries. So, Sir, now, this 5,000 million tonnes is available but there is no response from some State Governments even to lift the stock. Even we are prepared to give more stock to the tiny consumers and we are giving at a price at an additional cost of 20 per cent over the notified price. The price is only *(Interruptions)*.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, कोयला मंत्रालय में पूरे का पूरा घोटाला है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक को प्रश्न पूछने दीजिए।...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। एक सदस्य क्वेश्चन कर रहा है, आप बीच में खड़े हो रहे हैं, आप बैठिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: This 5 million tonnes coal is high ash quality, Sir. It is of no use to the industrial purpose. That is the reason. *(Interruptions)*

DR. DASARI NARAYAN RAO: Please hear the reason. *(Interruptions)* Here, it is not the question of ash content. *(Interruptions)* Sir, whatever questions they ask, the same question I will reply. The notified price is for the power generation and for the cement generation, because it should not affect the economy of the nation. So, the notified price plus

20 per cent is the floor price for the small consumers, but there is a request from the small consumers and we are considering it. I think, we are going to reduce it in the next meeting.

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, कोयला मंत्रालय में पूरे का पूरा घोटाला भरा हुआ है। मंत्रालय का काम-काज आप देखिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं कर रहा। Nothing will go on record except questions. Please put your question.

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, मेरा मंत्री महोदय से सीधा सवाल है कि आपके यहां लोकल सेल के लिए जो पैसा लोग बांधे थे, उसकी पोजीशन क्या है? आपने ई-ऑक्शन तो लागू कर दिया, लेकिन लोकल सेल के लिए, गरीब लोगों द्वारा शमशान घाट में शव-दाह के लिए कोयला खरीदने के लिए लोकल सेल के लिए जो पैसा बांधा गया था, उसकी स्थिति क्या है?

श्री महेन्द्र मोहन: सर, 680 बोगस कम्पनियों का क्या हुआ, उन पर क्या कार्रवाई की गई?

DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, for the small consumers, through Government agencies, they can draw coal. I think, last time also our hon. Member informed me that some deposits were taken from some consumers and we are looking into it, and I will get the details to the hon. Member.

श्री महेन्द्र मोहन: सर, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि 680 बोगस कम्पनियां पाई गई हैं, उन पर क्या ऐक्शन लिया गया है?

DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, it is under the State Governments' control and State Governments will recommend the companies; so, whatever companies we found bogus, we stopped giving linkage and coal supplies to those companies.

श्री अजय मारू: महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ई-ऑक्शन में जो आपने पिछले महीने 45 लाख टन कोयला आबंटित किया था, क्योंकि ई-ऑक्शन में रेट अधिक है, इसलिए उसमें से मात्र 11 लाख टन कोयला उठाया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ई-ऑक्शन के रेट को फ्लोर प्राइस से नीचे करने की इच्छा जता रहे हैं?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: E-auction is free.

श्री अजय मारू: ई-ऑक्शन में कोई माल ही नहीं उठाता, वही बोल रहा हूं।

श्री शिबु सोरेन: ऐसी बात नहीं है, ई-ऑक्शन में बहुत माल तो लोगों ने उठाया है ... (व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: 11 लाख टन आप खुद ही बोल रहे हैं।

श्री अजय मारू: मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

श्री शिबु सोरेन: और फ्लोर प्राइस पर, जो 20 प्रतिशत अधिक है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं ताकि उनको सुविधा दी जा सके।

श्री अजय मारू: क्या परसैंटेज, क्या कमी होगी उसमें?

श्री शिबु सोरेन: उस पर विचार होगा, तब बताएंगे।

श्री अजय मारू: विचार कब होगा? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: पहले परसैंटेज तय होगी, फिर विचार होगा। Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Installation of Mobile BTS at Azamgarh

*243. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the number of mobile Base Transmitting Station (BTS) that are proposed to be installed in Azamgarh District;

(b) the names of places where land has been allotted for this purpose in Azamgarh District;

(c) whether mobile BTS at Jainagar in Azamgarh District is under construction;

(d) if so, the details of progress made in this regard; and

(e) by when this mobile BTS at Jainagar will be completed?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): (a) Sir, in district Azamgarh, Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) has planned a total of 40 BTSs for the current financial year. Out of these, 37 BTSs have already been commissioned and another three to be commissioned during the current financial year. Further, private telecom service providers are also to install 28 BTSs.